राजधानी रांची में सोमवार को बड़ी संख्या में बंगभाषी जुटे. उनके हाथों में मांगों के समर्थन में लिखी तख्तियां थी. झारखंड के अलग -अलग हिस्सों से ठंड के बावजूद वे अपने सांस्कृतिक स्वाभिमान की रक्षा के लिए पहुंचे थे. पूछने पर समुदाय के लोगों ने कहा कि यह हमारे हक अधिकार की लड़ाई है. पिछले कई वर्षों से हम यह लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और हम मिलने तक लड़ते रहेंगे. हमारी मांग जायज है. हमारी भाषा संस्कृति का इतिहास बहुत पुराना है. हम बड़ी संख्या में राज्य के विभिन्न जिलों में लंबे समय से रहते आए हैं. देश में स्वतंत्रता आंदोलनों से लेकर हर जगह बंगभाषियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इसके बावजूद झारखंड में बांग्ला भाषी वर्षों से उपेक्षित बने हुए हैं. झारखंड में हमें हर तरह की सुविधा व सम्मान मिलना चाहिए. जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं. पर सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है. सरकार की इस लापरवाही से हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ गया है . जिसे हम बांगलाभाषी कतई बर्दाशत नही करेंगे. आजादी के पहले और अविभाजित बिहार के समय भी हमारा मान था. पर झारखंड गठन के बाद हमारी उपेक्षा शुरू हो गई. हमलोग आज यहां अपनी बात कहने आए हैं. अपनी मांगों के बारे में बंगभाषियों ने कहा कि सरकार बोर्ड व निगम में भी हमें प्राथमिकता दे. सरकार केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के अनुसार सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में बंगला भाषा की पढाई शुरू करे, राज्य के सभी स्कूलों में बांग्ला शिक्षक की नियुक्ति करने, बंगला अकादमी की स्थापना करने, राज्य के हर रेलवे स्टेशन में बंगला भाषा में स्टेशन का नाम अंकित करने समेत अन्य मांग शामिल हैं. अगर सरकार हमारी मांगों पर गौर नहीं करेगी तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा. शुभम संदेश की टीम ने बंगभाषियों के इस आंदोलन को कवर किया है. पेश है रिपोर्ट...

अपनी भाषा-संस्कृति की पहचान और हक के लिए रांची में बड़ी संख्या में जुटे बंगभाषी

हक मिलने तक लड़ाई लड़ते रहेंगे

- भाषा-संस्कृति की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करेंगे बंगभाषी
- झारखंड में बड़ी संख्या में रहते हैं बांग्लाभाषी
- हमारी मांगें जायज हैं, हमारा पुराना इतिहास रहा है
- सरकार की उपेक्षा से सांस्कृतिक बिरासत को खतरा
- स्कूलों में हो बांग्ला भाषा की पढ़ाई, शिक्षकों की भी बहाली की जाए

अपनी मांगों को लेकर बांग्ला भाषियों ने किया राजभवन मार्च

संवाददाता। रांची

अपने आठ सूत्री मांगों को लेकर झारखंड बांग्लाभाषी उन्नयन समिति ने राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया दिया. इससे पूरे राज्य भर से आए हजारों की संख्या में बांग्लाभाषियों ने मोरहाबादी मैदान से राजभवन तक मार्च किया. समिति के सभापति अचिंतम गुप्ता ने कहा कि झारखंड राज्य गठन के बाद साजिश के तहत प्रदेश में बंगला भाषा का अस्तित्व मिटाने का प्रयास किया जा रहा है. पहले तो बंग्लाभाषा की पढ़ाई बंद कर दी गई. उसके बाद आयोग के गठन में भी बांग्ला भाषा के लोगों को स्थान नहीं दिया गया. अब विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर भी बंगला भाषा में लिखे गए नामों को हटा दिया गया. जबकि राज्य में 42 प्रतिशत यानी एक करोड़ से भी ज्यादा लोग बांग्ला बोलते हैं.

राज्यपाल को सौंपे आठ सूत्री मांगों में कक्षाओं में नए सिरे से बांग्ला भाषा की पढ़ाई प्रारंभ करने, बांग्ला अकादमी की स्थापना करने, प्रत्येक विद्यालय में बांग्ला शिक्षक की नियुक्ति करने, अल्पसंख्यक आयोग में पूर्व की भांति भाषाई अल्पसंख्यकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने, प्रत्येक रेलवे स्टेशनों पर पूर्व की तरह बांग्ला भाषा में स्टेशन का नाम अंकित करने और चांडिल में वर्ष 2019 में असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त किए गए शहीद खुदीराम बोस की प्रतिमा को स्थापित करने की मांग शामिल हैं.धरने में पूरे प्रदेश से प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें रेखा मंडल, रीना मंडल , पंपा सेन विश्वास, सम्राट चौधरी , संजीत आचार्य, गौतम चटर्जी समेत कई लोग शामिल रहे.

सबने अन्याय ही किया है

समिति के अध्यक्ष बेंगू ठाकुर ने कहा कि अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं सबने बांग्ला भाषा के साथ अन्याय ही किया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा और जो भी सरकार बांग्ला भाषा को नजरअंदाज करेगी उसे सबक सिखाया जाएगा .अगर हमारे मांगों को नहीं माना गया है तो आने वाले समय में जोरदार आंदोलन होगा और लोकसभ– विधानसभा के चुनावों में बांग्ला भाषा भाषियों की अवहेलना का फल सरकार को भुगतना पड़ेगा.

सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा : पायल बनर्जी

सोनाहातूकी रहने वाली पायल बनर्जी का कहना है कि आज झारखंड में बंगाली समुदाय अस्तित्व के लिए अपनी आवाज उठानी पड़ रही है. यह एक स्वस्थ सरकार की पहचान नहीं है, बंगाली समाज ने न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश एवं विश्व को एक से एक महान व्यक्तित्व दिया है. यह बात किसी से छुपी नहीं है. आज हम सब स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं, परंतु उनकी मातृभाषा बंगाली को झारखंड में सम्मान नहीं दे पा रहे हैं. यह झारखंड सरकार के लिए बहुत निराशाजनक बात है. आशा है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेगी और बंग समाज को निराश नहीं करेगी.

झारखंड का बंगाल से पुराना रिश्ता : रतन मिश्रा

सोनाहातू के रतन मिश्रा कहते हैं कि झारखंड का सीमावर्ती क्षेत्र बंगाल होने के कारण बंगालियों का झारखंडियों से वर्षों से लगाव रहा है. कई वर्षों से झारखंड में बंगाली समाज के लोग रहते हैं. बंगाली समाज को आगे लाने के लिए सरकार को अग्रसर होना चाहिए. बंगाली समाज की संस्कृति और परंपरा बंगाल से जुड़ी हुई है. सभी विद्यालयों में बांग्ला की पढ़ाई होनी चाहिए एवं सभी स्टेशन के नाम बांग्ला में होने चाहिए.

भाषा के साथ अन्याय न करे सरकार : रामरंजन

सोनाहातू पंडाडीह के रहने वाले रामरंजन चटर्जी (भक्ति) का कहना है कि आज आधा झारखंड और दुनिया के 27 हजार करोड़ जनता सातवीं सबसे ज्यादा बोली जाने भाषा बांग्ला है. बहुत सारे स्कूलों में अन्य भाषा पढ़ाई जा रही है पर बांग्ला भाषा के साथ ऐसा क्यों. हमें आप आरक्षण नहीं दे पा रहे मत दीजिए दूसरी सरकारी कल्याणकारी योजना नहीं देना चाहते हैं मत दीजिए, लेकिन सरकार से सिर्फ आग्रह ये है कि आप कुछ दे नहीं पा रहे हैं तो एक ऐसी भाषा जो हर किसी के दिल को सुकून देती हो वैसे मधुर भाषा के साथ ऐसा अन्याय न करे कि बंगभाषी सड़क से सदन तक पहुंच जाए.

विद्यालयों में बांग्ला की पढ़ाई अनिवार्य हो : दिनेश

सोनाहातू के रहने वाले दिनेश का कहना है कि झारखंड के सभी विद्यालयों में बांग्ला भाषा की पढ़ाई होनी चाहिए. हिंदी की तरह बांग्ला भाषा को अनिवार्य करना चाहिए. झारखंड कभी बंगाल का ही हिस्सा था. इस कारण झारखंड के अधिकतर इलाकों में बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं . उनकी संस्कृति और रीति रिवाज को बचाए रखने के लिए बांग्ला भाषा का स्थायी होना बहुत जरूरी है.

भाषा संस्कृति को सरकार ठेस न पहुंचाए: बुलू मुखर्जी

सोनाहातू निवासी बुलु मुखर्जी का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जानी वाली मुख्य 10 भाषाओं में एक है बांग्ला भाषा, जिसके लुप्त होने से भाषा संस्कृति पर इसका बुरा असर हो सकता है. खास कर एक ऐसा राज्य जहां 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग आपस में इस भाषा में बात कर भाईचारे का अद्भुत मिसाल पेश करते हैं. बंगला भाषा के मधुर गीत सभी को राजधानी से लेके गांव, कस्बों तक सुनाई देता है. अतः इस भाषा को यथावत रखते हुए बंग भाषियों का सम्मान करें.

सरकार उचित प्राथमिकता दें: गणेश तिवारी

गणेश तिवारी का कहना है कि झारखंड सरकार बांग्ला भाषा की संस्कृति को बचाए रखने के लिए एवं बांग्ला समाज को ऊपर ले जाने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए. बांग्ला वासियों को बांग्ला भाषा का प्रयोग नहीं होने से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इसलिए सरकार को इस भाषा को प्राथमिकता देनी चाहिए. इससे बांग्ला भाषा की संस्कृति की भी रक्षा हो पाएगी.

बांग्ला वासियों की मांगें जायज है: ठाकुर प्रसाद

राहेके रहने वाले ठाकुर प्रसाद का कहना है कि हमारा परिवार 100 वर्षों से झारखंड में रह रहा है. झारखंड में इस तरह के हजारों परिवार हैं जो वर्षों से परंपरागत रूप से बांग्ला भाषा को समझते हुए बांग्ला भाषा को सम्मान देते हैं. बांग्ला भाषा के अधिकार एवं उचित सामान के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है. सभी का अधिकार एक समान है. बंगाली समाज को भी हक और अधिकार मिलना चाहिए. एकजुट होकर अपनी भाषा संस्कृति और विरासत को बचाए रखने के लिए लड़ाई लड़नी ही चाहिए.

रांची

बांग्ला सिर्फ नाम की दूसरी राजभाषा :अचिंतम गुप्ता

झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति के सभापति अचिंतम गुप्ता का कहना है कि सरकार ने बांग्ला को दूसरी राजभाषा का दर्जा तो दिया है लेकिन ये सिर्फ नाम का है. बांग्ला भाषा में शिक्षक नहीं हैं . बच्चे बांग्ला सीख नहीं रहे हैं. पूरे राज्य में बांग्लाभाषी 42 प्रतिशत हैं फिर भी ये स्थिती है. राज्यपाल से हमें पूरी उम्मीद है कि इस विषय में ये संज्ञान लेंगे और बांग्ला भाषा को बचाने के लिए सरकार को निर्देश देंगे.

राज्य में एक करोड़ से अधिक बांग्लाभाषी : बेंगु ठाकुर

झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति के प्रदेश अध्यक्ष बेंगु ठाकुर का कहना है कि झारखंड में एक करोड़ से अधिक बांग्ला भाषी हैं 26 जाति के लोगों की मातृषाषा बंगाली है . अभी तक सरकारों ने हमें छला है बांग्ला के हित में जो बात नहीं करेगा उसे हम सबक सीखा देंगे.

उग्र प्रदर्शन के लिए मजबूर न करे :रेखा मंडल

झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति की कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुकीं रेखा मंडल का कहना है कि बांग्ला भाषा हमारा मूलभूत अधिकार है और ये अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता इसके लिए हम सड़क पर उतर चुके हैं अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम उग्र प्रदर्शन के लिए मजबूर हो जाएंगे.

लड़ाई मातृभाषा बांग्ला के लिए है : पंपा सेन विश्वास

रांची की पंपा सेन विश्वास का कहना है कि बांग्ला हमारी मातृभाषा है और इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है बांग्ला स्कूलों में पढ़ाई हो और इसके किताब मिलें यही सरकार से मांग है. सरकार को बांग्ला भाषा को लेकर गंभीरता दिखानी ही पड़ेगी. यह बांग्लाभाषियों के स्वाभिमान की बात है.

एकीकृत बिहार की स्थिति अच्छी थी : साधुचरण पाल

घाटशिला के साधुचरण पाल का कहना है कि एकीकृत बिहार में इससे अच्छी स्थिति थी. स्कूलों में बंगाल की पढ़ाई होती थी स्टेशनों में बांग्ला में नाम रहता था. बस स्टैंड में नाम रहता था, लेकिन एक षडयंत्र के तहत इसे हटा दिया गया है इसे पुनः बहाल किया जाए.

अपना अधिकार हम लेकर रहेंगे: पूरण मुखर्जी

पूर्वी सिंहभूम के पूरण मुखर्जी का कहना है कि अभी तक बांग्ला भाषी अपने अधिकारों से वंचित रहे हैं लेकिन अब ऐसा नहीं हो गा और हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े.

आजादी के लिए बिगुल फूंका था : तापस चटर्जी

झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष तापस चटर्जी बर्धमान के रहने वाले हैं और इनका कहना है कि बंगाली समाज एकजुट हो कर ये प्रदर्शन कर रहा है और ये सरकार को चेतावनी हैं कि बंगाली समाज को नजरअंदाज नहीं करे. झारखंड का गठन होने के बाद भी ऐसा होना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. बंगालियों ने देश की आजादी की लड़ाई में सबसे पहले बिगुल फूंका था और आज भी अपना अधिकार लेकर रहेंगे.

बांग्ला मेरी भाषा, बांग्ला मेरा परिचय : रीना मंडल

रांची की रहने वाली रीना मंडल का मानना है कि बांग्ला मेरी भाषा बांग्ला मेरा परिचय है. यह अधिकार हम छीनकर रहेंगे. अब तक बहुत सह लिया अब और नहीं सह सकते. सरकार को बांग्ला भाषा के साथ न्याय करना ही होगा. नहीं तो बंगाली समुदाय का सरकार के खिलाफ विरोध जारी रहेगा.

न किताब है, न शिक्षक और न ही पढ़ाई : वर्षा मुखर्जी

रांची की वर्षा मुखर्जी का कहना है कि किताब है, ना शिक्षक है और ना ही ही पढ़ाई हो रही है. बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, चौक चौराहों में कहीं बांग्ला नहीं दिखता है सिर्फ नाम के लिए बांग्ला को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है . ऐसा नहीं चलेगा. सरकार को इस दिशा में पहल करनी पड़ेगी. हम अपना अधिकार ले कर ही रहेंगे.

बांग्ला की अवहेलना बर्दाश्त नहीं : संजीत आचार्य

धनबाद के संजीत आचार्य का कहना है कि झारखंड में बांग्ला भाषा की अवहेलना करना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अब तक की सरकारों ने बांग्ला भाषा के साथ अन्याय ही किया है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा बांग्ला भाषी सचेत हो गए। अगर हमारे मांगों को नहीं माना गया है तो आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बांग्ला भाषा भाषियों के बिना कोई भी सरकार नहीं बन सकती.

राज्यपाल से हमें पूरी उम्मीद : पंपा मुखर्जी

जमशेदपुर की रहने वाली पंपा मुखर्जी का कहना है कि हमने अपनी मांगों से राज्यपाल को अवगत कराया है और हमें पूरी उम्मीद है कि महामहिम इस मामले में सरकार को निर्देश देंगे. साथ ही बांग्ला भाषा के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

बांग्ला भाषा का विकास करना होगा : सम्राट चौधरी

धनबाद के सम्राट चौधरी का कहना है कि बांग्ला में पढ़ाई नहीं होगी तो बांग्ला भाषा का विकास नहीं होगा. इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि बांग्ला का विकास करने में कोताही न बरते.

जमशेदपुर

अकादमी की स्थापना जरूरी : बीथिका अधर्जी

कदमा निवासी बीथिका अधर्जी ने कहा कि राज्य में बंग भाषियों की संख्या काफी ज्यादा है. झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से स्कूलों में बांग्ला पुस्तक मिलना बंद हो गया है. बांग्ला को पूर्ण रूप से द्वितीय राजभाषा का दर्जा भी नहीं मिला. राज्य में बांग्ला पढ़ाई का पाठ्यक्रम ही नहीं है, सरकार किताब भी प्रकाशित नहीं करवाती है, शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है. बांग्ला माध्यम के सरकारी स्कूलों को हिंदी माध्यम में बदल दिया गया है. राज्य में बांग्ला भाषा साहित्य और संस्कृति के विकास के लिए बांग्ला अकादमी की स्थापना करनी चाहिए.

स्कूलों में बंगला की पढ़ाई शुरू हो : पोम्पा दत्ता

पोम्पा दत्ता ने कहा कि झारखंड में बांग्ला भाषियों की उपेक्षा से बंगाली समुदाय में नाराजगी है. सरकार द्वारा किसी तरह की पहल नहीं किए जाने से बांग्ला भाषियों का अस्तित्व समाप्त होने की कगार पर है, जिसे बचाने की जरूरत है. इस राज्य में बंगालियों की अच्छी संख्या है. राज्य के सभी स्कूलों में बंगला की पढ़ाई शुरू होनी चाहिए. साथ ही स्टेशनों का नाम भी बांग्ला में लिखा जाना चाहिए. बंग भाषियों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

सम्मान के लिए संगठन आंदोलनरत : शेली दास

परसुडीह की रहने वाली और गृहिणी शेली दास ने कहा कि बांग्ला भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान देने के लिए संगठन आंदोलनरत है. बांग्ला भाषा की रक्षा को लेकर विभिन्न बंगाली संगठन से जुड़े लोगों सोमवार को राजभवन के समक्ष एकत्रित हुए हैं. अपनी भाषा संस्कृति की रक्षा के लिए हम सभी एकजुट हो रहे हैं. बांग्ला भाषा में रेलवे स्टेशनों का नाम, स्कूल व कॉलेज में पढ़ाई तथा सरकार अपने विभिन्न निगम में बंगाली समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करें अन्यथा इसके लिए जोरदार आंदोलन किया जाएगा.

स्टेशनों के नाम बांग्ला में लिखे : दीप एस पॉल

आदित्यपुर निवासी दीप एस पॉल ने कहा कि झारखंड में बंग भाषा-भाषियों की संख्या काफी अधिक हैं, इसलिए बंगाली समुदाय के लोगों को सम्मान मिलना चाहिए. कम से कम स्कूल कालेजों में बांग्ला भाषा में पढ़ाई होनी चाहिए. बोर्ड -निगम में भी बंगभाषियों को उचित प्रतिनिधित्व मिलनी चाहिए. भारत सरकार स्टेशनों के नाम बांग्ला में लिखे, चूंकि बंगभाषियों को स्टेशनों के नाम पढ़ने में परेशानी होती है. अपनी मांगों को लेकर राजभवन के सामने धरना दिया जा रहा हैं.

मनोहरपुर

बांग्ला भाषियों के साथ अन्याय : श्रवण कुमार घोष

मनोहरपुर निवासी श्रवण कुमार घोष उर्फ लालटू दा का कहना है कि झारखंड अलग राज्य गठन के बाद राज्य के लगभग सवा करोड़ बांग्ला भाषियों को उम्मीद थी कि राज्य सरकार बांग्ला माध्यम से पठन-पाठन व्यवस्था को दुरुस्त करेगी. सथा ही हर क्षेत्र में समाज की भागीदारी मिलेगी.लेकिन राज्य में इसके विपरीत हो रहा है. इस समय बांग्ला माध्यम के स्कूल-कॉलेज बंद हो गए हैं. राज्य की द्वितीय राजभाषा के शिक्षकों की घोर कमी है. स्कूलों में बांग्ला पुस्तकें भी नहीं है.जिससे बंगाली समाज अपने आप को घोर उपेक्षित महसूस कर रहा है. जिससे समाज के लोग पश्चिम बंगाल हो या अन्य राज्यों में पलायन को मजबूर हो रहे हैं.

सदन तक आवाज बुलंद करेंगे : सोमेनचंद्र हाजरा

मनोहरपुर के जाने माने उद्योगपति एवं समाजसेवी सोमेनचंद्र हाजरा का कहना है कि बंगाल से झारखंड सटे होने के कारण बंगालीभाषी लोग यहां आते जाते हैं. झारखंड के हर जिले में बंगलाभाषी के लोग अधिक मात्रा में निवास करते हैं. झारखंड और बंगाल में व्यवसाय करने वाले लोग भी यहां आना जाना करते हैं. इसलिये यहां सभी जगहों पर बांग्लाभाषियों को प्रतिनिधित्व करने को मिले, जिससे वह अपने समाज और देश के विकाश पर अपनी प्रबुद्धता और अखंडता पर कार्य कर सके. बंगाल से आने वाले कई ऐसे यात्री हैं, जिन्हें सिर्फ बंगला लिपि का ज्ञान है. इसलिए यहां सभी जगह बांग्ला भाषा का भी उपयोग हो. साथ ही हमारी मांग है कि झारखंड के हर रेलवे स्टेशन का नाम बांग्ला लिपि में लिखा जाए. इसके लिये हम सड़क से सदन तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम करेंगे.

स्टेशनों के नाम भी बांग्ला में लिखा हो : सजल

व्यवसाई परिवार से जुड़े सजल रंजन चावली का कहना है कि झारखंड में बंगाली समाज का उद्योग धंधे में अहम् योगदान है.हज़ारो की संख्या में स्थानीय लोगों को रोज़गार प्राप्त है.चूंकि बिहार से अलग झारखंड पहले बंगाल का हिस्सा था.जिससे यहां भारी संख्या में बंगाली समाज के लोग निवास करते है.जिससे हमलोगों का बंगाल के अलावा झारखंड की इस पावन धरती से भी हमसबों का आत्मीय जुड़ाव है.चूंकि बंगाल से सटे होने के कारण ब्यापार,शादी व्याह सामाजिक रिश्ता के अटूट बंधनों से जुड़ा हुआ है.वहीं लोगों का ब्यापार,सामाजिक रिश्ता हो या टूरिस्ट के हैसियत से आना जाना होता है.ऐसे में रेलवे स्टेशनों का नाम बांग्ला में भी लिखा जाना चाहिए. बंगाल से झारखंड में काफी संख्या में टूरिस्ट एवं अन्य लोग ट्रेनों से आते जाते हैं.

बांग्ला अकादमी का गठन होना चाहिए: श्रीजीत हाजरा

युवा व्यवसाई श्रीजीत हाजरा ने कहा कि झारखंड के बांग्लाभाषी चाहते हैं कि झारखंड में भी बांग्ला आकादमी का गठन हो. झारखंड व बिहार पहले बंगाल का ही हिस्सा था. यह 22 मार्च 1911 को बंगाल से अलग हुआ था. इस कारण झारखंड में काफी संख्या में बंगाली समुदाय के लोग यहां रहते हैं. उनकी हितों की भी रक्षा होनी चाहिए तथा स्कूलों व कॉलेजो में भी बंगला की पढ़ाई होनी चाहिए.ताकि बंगाली समाज का उत्थान व उनकी संस्कृति की रक्षा हो सके.

बड़ी संख्या में बांग्लाभाषी उपेक्षित : जोली हाजरा

गृहिणी जोली हाजरा कहतीं हैं कि झारखंड पूर्व से बंगभाषी क्षेत्र रहा है. आज भी 42 फीसदी बंगभाषी झारखंड में रहते हैं.अलग झारखंड राज्य निर्माण में बंगाली समुदायों का अहम योगदान है.बावजूद बंगभाषी समाज आज भी उपेक्षित है.राज्य में बंगभाषी लोगों को जो सम्मान मिलना चाहिए.उस हक से वंचित है.जिससे समाज अपने आपको ठगा महसूस कर रहा है.चूंकि बांग्ला संस्कृति देश की समृद्ध व सबसे पुरानी संस्कृति है.कम से कम स्कूल, कालेजों में बांग्ला भाषा की पढ़ाई होनी ही चाहिए. बोर्ड -निगम में बंगभाषियों को उचित प्रतिनिधित्व मिले. स्टेशनों के नाम बांग्ला में होने चाहिए.

पढ़ाने के लिए अलग से शिक्षक जरूरी : शंकर बोस

शंकर बोस और उनकी पत्नी सुनीता कंठ का कहना है कि बांग्ला भाषा और उसके इतिहास के बारे में बच्चों को जानना बेहद जरूरी है, इसलिए सभी स्कूलों में बांग्ला भाषा की पढ़ाई शुरू करना और बांग्ला एकेडमी का गठन किया जाना चाहिए. पूर्व की व्यवस्था को जारी रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को इसकी जानकारी हो. समय के साथ काफी कुछ बदल गया है. इस आंदोलन में राजनीति न हो यह भी ध्यान रखने की जरूरत है.

घाटशिला

राज्य में बांग्ला भाषियों की उपेक्षा : मौसमी पाल

घाटशिला कालेज की छात्रा मौसमी पाल ने कहा कि झारखंड में बांग्ला भाषियों की उपेक्षा हो रही है. उनका की झारखंड सरकार को बंगाली समाज के लोगों को उचित सम्मान देने की दिशा में पहल करनी चाहिए. घाटशिला अनुमंडल मुख्यालय होने के बावजूद महाविद्यालय में बांग्ला विषय से पीजी की पढ़ाई नहीं होती. जबकि बहरागोड़ा प्रखंड मुख्यालय का शहर है वहां के कॉलेज में बांग्ला विषय से पीजी की पढ़ाई हो रही है. इसके अलावा राज्य स्थापना से पूर्व सभी रेलवे स्टेशन पर बांग्ला बांग्ला में स्टेशन का नाम लिखा हुआ था. राज्य गठन के बाद मिटा दिया गया.

बांग्ला भाषियों के साथ हो रहा अन्याय : परिमल

घाटशिला प्रखंड के दीघा चापड़ी गांव के रहने वाले व्यवसाय परिमल महतो ने कहा कि पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल होने के कारण यहां के सभी समाज के लोग बांग्ला भाषा में बोलचाल करते हैं. बंगाली संगठन के द्वारा वर्षों से अपनी मांग को लेकर आंदोलन करते आ रहे हैं. उनकी मांगे जायज है. बांग्ला को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए. स्कूल कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति हो ताकि बंगाल की पढ़ाई सुचारू रूप से किया जा सके.

उपलब्ध कराई जाती थी बांग्ला पुस्तकें : अवनी

घाटशिला गोपालपुर निवासी व्यवसायी अवनी गिरी मैं कहा कि झारखंड स्थापना के पहले से बंगाली समुदाय द्वारा बांग्ला में पठन-पाठन के लिए स्कूलों में बांग्ला भाषा की किताबें उपलब्ध कराने, बोर्ड निगम में प्राथमिकता देने सहित कई मांगें विभिन्न बंगाली संगठनों के द्वारा उठाया जाता रहा है. जबकि बिहार के समय स्कूलों में बांग्ला किताबें उपलब्ध हुआ करती थी. लेकिन अब किताबें मिलने बंद हो गई है. इसके कारण समाज के लोगों में आक्रोश है. इसे लेकर सोमवार को रांची के राजभवन स्थित धरना प्रदर्शन भी किया गया.

बोकारो

हर आंदोलन में बंगालियों की भूमिका अहम : लालेन्दु

बोकारो जिले के कसमार प्रखंड के सुरजुडीह निवासी लालेन्दु मुखर्जी ने बताया कि देश में स्वतंत्रता आंदोलनों से लेकर हर जगह बंगभाषियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इसके बावजूद झारखंड में बांग्ला भाषी वर्षों से उपेक्षित बने हुए हैं. झारखंड में हमें हर तरह की सुविधा व सम्मान मिलना चाहिए. इसके लिए आंदोलन भी करना पड़े, तो मंजूर है. बांग्ला भाषा को हर हाल में हक अधिकार सरकार को देना होगा. इसके लिए पूरे राज्य में और हर जिले में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन भी चल रहा है.

बांग्ला शिक्षक की हो बहाली : सरोज कुमार

बोकारो जिले के जरीडीह प्रखंड के बहादुरपुर निवासी सरोज कुमार ने बताया कि जब 20 साल पहले तक सभी सरकारी स्कूलों में बांग्ला भाषा की पढ़ाई हो रही थी, तो उसे बंद करने की क्या जरूरत थी. सरकार को अविलंब बांग्ला शिक्षक की बहाली करनी चाहिए, ताकि बंगभाषी के बच्चे बांग्ला भाषा की पढ़ाई कर सके. बांग्ला भाषा को सुनियोजित तरीके से झारखंड में खत्म करने के तहत एक साजिश चल रही है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे.

बोर्ड व निगम में भी मिले प्राथमिकता : प्रताप पाल

बोकारो जिले के कसमार प्रखंड के चट्टी निवासी प्रताप पाल ने बताया कि बांग्ला भाषियों को सरकार के बोर्ड व निगम में भी प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि बंग भाषियों की तादाद पूरे राज्य में सभी जिलों में है. इसके बावजूद अगर सरकार तरजीह नहीं देती है, तो इसके लिए आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने बताया कि हर जिले में अब बंग भाषियों की कमिटी को मजबूत बनाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है.

कॉलेज स्तर तक अनिवार्य हो बांग्ला भाषा : कमलेश

कसमार प्रखंड के धधकिया निवासी कमलेश मुखर्जी ने बताया कि झारखंड के हर जिले में सभी सरकारी स्कूलों में प्राथमिक से लेकर कॉलेज स्तर तक हर हाल में बांग्ला भाषा की पढ़ाई सुनिश्चित हो, इसके लिए बंग भाषी जनप्रतिनिधियों को भी संवेदनशील होना चाहिए. पता नहीं झारखंड सरकार हमारी मांगों को क्यों दरकिनार कर रही है. उन्होंने बताया कि अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन करते रहेंगे.

चांडिल

रेलवे स्टेशनों के नाम बांग्ला में लिखे जाएं : प्रकाश

सिंहभूम कॉलेज चांडिल के छात्र प्रकाश कुमार ने कहा कि झारखंड के बांग्ला भाषी लोग चाहते हैं कि रेलवे स्टेशनों का नाम बांग्ला में भी लिखा जाए. स्कूलों में बांग्ला पुस्तक व शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और सभी स्कूलों में बांग्ला भाषा की पढ़ाई शुरू हो. बांग्ला भाषा की पढ़ाई बंद होने के बाद बंग भाषियों की भाषा-संस्कृति पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है. सरकार राज्य में अविलंब बांग्ला अकादमी का गठन करें. इन मांगों को लेकर हमेशा आवाज बुलंद की जा रही है, लेकिन सरकार उदासीन रवैया अपना रही है. सरकार को प्राथमिक स्तर में मातृभाषा बंगाल में पढ़ाई शुरू करवाने की जरूरत है.

झारखंड के स्कूलों में बांग्ला पुस्तकें नहीं : नीलम

सिंहभूम कॉलेज चांडिल की छात्रा नीलम भगत ने कहा कि सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होगी. सरकार के इस कथनी का धरातल पर विपरीत असर देखा जा रहा है. झारखंड के स्कूलों में बांग्ला की पुस्तकें नहीं है, यहां तक कि विद्यालय में बांग्ला पढ़ने के लिए शिक्षक मौजूद नहीं हैं. ऐसे में नई शिक्षा नीति धरातल पर लागू होता नहीं दिखाई दे रहा है. सरकार सिर्फ फीस बढ़ोत्तरी और सेमेस्टर सिस्टम ही लागू कर सकी है. सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द धरातल पर बांग्ला भाषा की पढ़ाई शुरू करने के लिए विद्यालयों में पुस्तक, शिक्षक, कर्मचारी की व्यवस्था करें.

बांग्ला भाषा की पढ़ाई पूरी तरह से लुप्त : शेफाली

सिंहभूम कॉलेज चांडिल की छात्रा शेफाली सिंह सरदार ने कहा कि चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में बांग्ला भाषा की पढ़ाई पूरी तरह से लुप्त हो गई है. अभी के विद्यार्थियों को बांग्ला भाषा का तनिक भी ज्ञान नहीं है. ऐसे में क्षेत्र से भाषा-संस्कृति का ह्रास हो रहा है. क्षेत्र में बंगाली कैलेंडर के अनुसार ही सभी पूजा-पाठ, शादी और बंगाली पंचांग के अनुसार ही शुभ मुहूर्त देखकर ही काम करते हैं. इसलिए अविलंब प्राथमिक स्तर से पीजी तक बांग्ला शिक्षकों की बहाली की जाए, प्रर्याप्त पुस्तकों का प्रकाशन कर एसे शिक्षण संस्थानों तक पहुंचाया जाए और मातृभाषा में पठन-पाठन शुरू किया जाए, नहीं तो बांग्ला भाषा क्षेत्र से लुप्त हो जाएगी.

भाषा को दरकिनार किया जा रहा है : कुमुदिनी

चांडिल निवासी कुमुदिनी प्रमाणिक ने कहा कि झारखंड बनने के साथ बांग्ला भाषा को दरकिनार कर दिया जा रहा है. सरकार का ऐसा कदम बांग्ला भाषियों के साथ अन्याय करने जैसा है. राज्य में बांग्ला भाषा के साथ जो रवैया अपनाया जा रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में बंगाली समुदाय के लोग अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाएंगे. सरकार को तत्काल राज्य के सभी स्कूलों में बांग्ला शिक्षकों की बहाली करते हुए बांग्ला पुस्तकों का प्रकाशन कर पढ़ाई शुरू की जानी चाहिए. बांग्ला भाषा की पढ़ाई बंद होने के बाद बांग्ला पंचाग पढ़ने के लिए अब गिने चुने लोग ही बचे हैं.

चाईबासा

बांग्ला को वास्तविक अधिकार मिले : त्रिशानु

झारखंड के समस्त बंग समुदाय द्वारा बंगला भाषा को वास्तविक रूप से क्रियान्वयन करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को रांची राजभवन के समक्ष महाधरना का आयोजन किया गया. महाधरना पर प्रतिक्रिया देते हुए बंग समुदाय से जुड़े त्रिशानु राय ने कहा कि झारखंड में बंगला भाषा को द्वितीय राज भाषा के रूप में स्वीकृति प्राप्त होने के बावजूद बंगला भाषा को राज्य में वास्तविक रूप से अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है.त्रिशानु राय ने आगे कहा कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के अनुसार सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में बंगला भाषा की पढ़ाई शुरू करने, राज्य के सभी स्कूलों में बंगला शिक्षक की नियुक्ति करने, बंगला अकादमी का स्थापना करने, राज्य के हर रेलवे स्टेशन में बंगला भाषा में स्टेशन का नाम अंकित करने समेत अन्य मांग शामिल हैं.मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार किए जाने की नितांत आवश्यकता है.

आदित्यपुर

झारखंड में 30 से 40 फीसदी बांग्लाभाषी, हमारी भाषा और संस्कृति को सम्मान मिलना ही चाहिए

हमारी भाषा का सम्मान नहीं कर रही : शशांक गांगुली

कर्मचारी महासंघ के नेता शशांक गांगुली का कहना है कि झारखंड में बांग्ला भाषियों की उपेक्षा हो रही है. बात भाषा की हो या संस्कृति की. यहां बांग्लाभाषी बहुसंख्यक हैं. लेकिन झारखंड सरकार उनकी भाषा और संस्कृति का सम्मान नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि झारखंड के बांग्लाभाषी भाषाई सम्मान चाहते हैं. भारत सरकार को बांग्ला भाषी बहुल क्षेत्रों में रेलवे स्टेशनों का नाम अन्य भाषाओं के साथ बांग्ला में भी लिखना चाहिए. झारखंड सरकार को स्कूलों में बांग्ला भाषा की पढ़ाई के लिए पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था करनी चाहिए. स्कूलों में बांग्ला भाषी शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए. बांग्ला भाषी क्षेत्रों के नगर निकायों में बंगभाषियों के लिए मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों की सीटें आरक्षित हो. इस बात की मांग काफी पहले से बंगभाषी कर रहे हैं. इसको लेकर भाषाई आंदोलन भी चल रहा है. झारखंड का अधिकतर क्षेत्र बंगभाषी है. इसलिये उनकी भाषा और संस्कृति का सम्मान होना चाहिए.

अब भी आधी आबादी बंगभाषियों की : प्रसेनजीत घोष

बंगीय एसोसिएशन के नेता प्रसेनजीत घोष का कहना है कि झारखंड बिहार बनने से पहले यह क्षेत्र बंगभाषी बहुल क्षेत्र रहा है. झारखंड में अब भी आधी आबादी बंगभाषियों की है. जमशेदपुर, चाईबासा, रांची, धनबाद, देवघर में बंगभाषियों की काफी संख्या है. इसलिए बंगभाषी लोगों को सम्मान मिलना चाहिए. कम से कम स्कूल कालेजों में बांग्ला भाषा में पढ़ाई होनी चाहिए. बोर्ड -निगम में भी बंगभाषियों को उचित प्रतिनिधित्व मिलनी चाहिए. भारत सरकार स्टेशनों के नाम बांग्ला में लिखे, चूंकि बंगभाषियों को स्टेशनों के नाम पढ़ने में परेशानी होती है. बंगीय एसोसिएशन के बैनर तले पहले से आंदोलन चल रहा है. सरकार हमारी मांगों की अनदेखी कर रही है. इससे बंगाली समुदाय काफी मर्माहत है. राज्य सरकार को इस दिशा में ध्यान देने की जरुरत है. ताकि बंगभाषी अपने को गौरांवित महसूस कर सके. इस समय बांग्ला समुदाय अपने सांस्कृतिक स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है.

धनबाद

नई पीढ़ी को इतिहास जानना जरूरी : पियाली चक्रवर्ती

धनबाद झरिया स्थित जामाडोबा को ऑपरेटिव कॉलोनी की रहने वाली पीयाली चक्रवर्ती ने कहा कि बांग्ला में भी काफी कुछ इतिहास है जिसे नई पीढ़ी पूरी तरह भूल गए है . सरकार को अविलंब सभी स्कूलों और कॉलेजों में हिन्दी और इंग्लिश भाषा की तरह बांग्ला भाषा की भी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए . ताकि नई पीढ़ी अपनी इतिहास को जान सके .

लोग इतिहास भूल रहे हैं : पार्थ भट्टाचार्य

धनबाद के हीरापुर स्थित दुर्गा मंदिर मुहल्ला के रहने वाले पार्थ भट्टाचार्य ने कहा कि बांग्ला भाषा की पढ़ाई बंद होने से झारखंड में एक प्रेम बंद हो गया है .जो बंगाली परिवार से है वह अपना इतिहास भूल गए हैं . इसका सबसे ज्यादा अशर नई पीढ़ियों पर पड़ रहा है .सरकार को अविलंब झारखंड में भी बांकी राज्यों की तरह बांग्ला भाषा को मान्यता दे देनी चाहिए. अन्यथा बांग्ला भाषा को लेकर किया जा रहा आंदोलन और तेज होगा.

बांग्लाभाषियों के साथ हो रहा भेदभाव : सोमनाथ

धनबाद झरिया स्थित जामाडोबा के रहने वाले सोमनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि झारखंड सरकार बांग्लाभाषियों के साथ भेदभाव कर रही है. सरकार की इस लापरवाही से हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ गया है. जिसे हम बांगलाभाषी कतई बर्दाश्त नही करेंगे. सरकार जल्द बांग्ला भाषा की पढ़ाई और शिक्षक की नियुक्ति करे .

दलील और खतियान बांग्ला में : भानु मुखर्जी

धनबाद धैया के रहने वाले भानु मुखर्जी ने कहा झारखंड को अलग राज्य का दर्जा देने के वर्षों बाद भी झारखंड का खतियान और दलील बांग्ला भाषा में ही है . बावजूद इसके झारखंड सरकार झारखंड में बांग्ला भाषा को दर्जा नहीं दे रहे हैं. सरकार इस पर पुनः विचार करे . अन्यथा बांग्लाभाषी इसका जवाब अपने मताधिकार से देंगे.

मातृभाषा का ज्ञान जानने का अधिकार : चंदन मुखर्जी

धनबाद हीरापुर के रहने वाले चंदन मुखर्जी ने कहा कि अपनी मातृभाषा और अपने समुदाय का ज्ञान सभी को जानने का मौलिक अधिकार है .सभी समुदाय का अपना अपना इतिहास होता है . लेकिन झारखंड सरकार बांग्ला भाषियों के साथ भेदभाव कर रही है .जिसके कारण युवा पीढ़ी अपनी मातृ भाषा से वंचित हो रहे हैं. सरकार को बांग्ला भाषियों की मांगें जल्द पूरी करनी चाहिए.इससे बंग समुदाय के लोगों को अपने गौरव का एहसास होगा और राज्य में बांग्ला भाषा संस्कृति की रक्षा हो पाएगी.

गिरिडीह

झारखंड में बांग्ला भाषा की उपेक्षा : कंचना सरकार

बेंगाबाद की कंचना सरकार ने कहा कि झारखंड में बांग्ला भाषाओं की उपेक्षा हो रही है . पूर्व में सभी रेलवे स्टेशन में में बांग्ला भाषा में स्टेशन का नाम लिखा हुआ रहता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है . उन्होंने कहा कि गिरिडीह जिले में कई स्कूल का नाम बंगला भाषा में है . लेकिन उस स्कूल में भी बंगला भाषा की पढ़ाई नहीं होती है . बांग्ला भाषी अपनी मांगों को लेकर जोरदार आंदोलन करेंगे .

बंगाली समाज को उचित सम्मान मिले : वर्षा राय

गांडेय प्रखंड के डहुआटांड़ निवासी वर्षा राय ने कहा कि झारखंड में बंगला समाज के लोगों की अच्छी संख्या है . इसके बाद भी समाज की उपेक्षा हो रही है . राज्य में सरकारी और निजी स्कूलों में पहले बंगला भाषा की पढ़ाई होती थी, लेकिन अब बंद हो गई है . उन्होंने कहा कि बंगाली समाज को उचित सम्मान नहीं मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा . बांग्ला समाज के लोगों को किसी भी क्षेत्र में उचित भागीदारी नहीं मिल रही है .

बंगाली समाज अधिकार से वंचित :मुकेश दत्ता

मुकेश दत्ता ने कहा कि बंगाली समाज के लोगों की किस राज्य में अच्छी जनसंख्या है . इसके बाद भी इस समाज की उपेक्षा हो रही है . जब से झारखंड अलग बना है बंगाली समाज को अधिकार से वंचित कर दिया गया है . इस समाज को उचित अधिकार दिलाने को लेकर किसी भी सरकार ने अब तक पहल नहीं की है . बंगाली समाज के लोग इस राज्य में आजादी के पहले से रह रहे हैं . राज्य की हेमंत सरकार को बांग्ला समाज को अधिकार दिलाने की दिशा में पहल करनी चाहिए .

बांग्ला 1000 वर्ष पुरानी भाषा है : अभिषेक मुखर्जी

डुमरी के अभिषेक मुखर्जी ने कहा कि बांग्ला 1000 वर्ष पुरानी भाषा है . इस समाज द्वारा बनाया गया मिठाई और रसगुल्ले राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित है . इसके बाद भी इस समाज की अपेक्षा समझ से परे है . रेलवे स्टेशनों पर बंगला भाषा में नाम नही लिखा जाना इस समाज की अपेक्षा है . उन्होंने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में बंगाल की पढ़ाई शुरू करवाने की मांग की है .